International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ग्रामीण गरीबी निवारण में मनरेगा एक तुलनात्मक अध्ययन झारखण्ड के बोकारो और रामगढ़ जिले के संदर्भ में

Gopal Kumar Das[1], Basanti Mathew Marlin[2]

[1]Research Scholar, Rabindranath Tagore University Bhopal M.P
[2]Research Guide & Co-Author, Rabindranath Tagore University Bhopal M.P

सारांश

झारखण्ड राज्य में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहकर कृषि कार्य को करते हुए अपना जीवन यापन करते है। लेकिन यहाँ की कृषि में उन्नत तकनीक के इस्तेमाल का अभाव तथा सिंचाई की सुविधा का अभाव है तथा यहाँ पर उद्योग धंधो की भी कमी है। परिणामस्वरूप यहाँ बेरोजगारी एवं गरीबी पायी जाती है।

गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने हेतू केन्द्र सरकार ने 2 फरवरी 2006 में एक योजना संचालित की जिन्हें मनरेगा के नाम से जानते है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी एवं गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस शोध पत्र मनरेगा के कार्यो का तुलनात्मक अध्ययन करने से बोकारो जिला तथा रामगढ़ जिले में रोजगार के अवसर महिलाओं की भागीदारी तथा कृषि के विकास से संबंधित का अध्ययन किया गया। आधारभूत संरचना के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये। आय बढ़ने से उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव आया। बोकारो जिला औद्योगिक प्रधान जिला होने के कारण मनरेगा का प्रभाव सीमित रहा। बोकारो तथा रामगढ़ दोनो ही जिलों में मनरेगा की कुछ प्रमुख समस्याओं का पता चला। इन समस्याओं को दूर करने हेतु उपयुक्त एवं उपयोगी सुझाव देने का प्रयास किया गया है। जिससे की मनरेगा योजना को अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाया जा सके।

शब्द कुंजी मनरेगा , झारखण्ड, गरीबी, बेरोजगारी, आधारभूत संरचना, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास।

भूमिका

झारखण्ड राज्य का निर्माण पूर्ववर्ती राज्य बिहार के 46 प्रतिशत भाग को काटकर 15 नबम्वर 2000 ई० को एक नया राज्य बनाया गया। यह देश का 28 वाँ राज्य है।

झाड़ियों एवं वनों की अधिकता के कारण इस प्रदेश को झारखण्ड नाम दिया गया। झारखण्ड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है।

झारखण्ड राज्य में कुल जनसंख्या का 75.95 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते है। यहाँ के लोगो का मुख्य धंधा कृषि है। करीब 70 प्रतिशत लोग कृषि में कार्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगकर अपना जीवन यापन करते है।

किन्तु यहाँ कृषि हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नही होने के कारण लोग साल भर खेती नही कर पाते। साथ ही यहाँ खनिजों की प्रचुरता रहने के बावजूद उद्योगों की कमी है। जिससे कारण लोग बेरोजगार एवं गरीब है। यहाँ कुल कृषि योग्य भूमि का सिर्फ 15 प्रतिशत भूमि में ही सिंचाई की सुविधा प्राप्त है।

ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को रोजगार देकर गरीबी मिटाने हेतू केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने कई कार्यक्रम संचालित किये जिनमे मनरेगा, कृषि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मुख्यमंत्री आर्शीवाद योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम मुख्य है।

झारखण्ड में गरीबी बेरोजगारी को दूर करने हेतु तथा ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत की कमी को दूर करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार एवं विकास हेतु केन्द्र में तत्कालीन कांग्रेस की यु पी ए सरकार ने 2 फरवरी 2006 से एक नयी योजना की शुरूआत किया जिसे नरेगा नाम दिया गया।

नरेगा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरूआत में 2006–2007 में देश के 200 सबसे गरीब जिले में लागू किया गया। 2007–2008 में योजना के विस्तार देते हुए देश के 130 जिले में लागू किया गया। इसके बाद योजना की मांग को देखते हुए डॉ० मनमोहन सिंह के परकार ने सारे देश के सभी जिलों में इस योजना को अप्रैल 2008 में लागू किया गया।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब एवं बरोजगार लोग को एक वितीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिन का अकुशल श्रम का रोजगार देकर ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसीत करते हुए दीर्घकालीन रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा महिलाओं दलित, पिछड़े, विकलांग वर्ग के लोगो को रोजगार की प्राथमिकता देते हुए आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान देना है।

ग्रामीण क्षेत्र में गरीब एवं बेरोजगार अकुशल व्यक्ति को रोजगार देने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है।
मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगो की आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में लोगो को रोजगार देने तथा कृषि के विकास, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण एवं लोगो की आजीविका के विकास के साथ–साथ बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण का कार्य करती है। जिसके परिणामस्वरूप रोजगाचर के प्रत्यक्ष अवसर बढ़ते है। आधारभूत संरचना के विकास से रोजगार के अन्य दीर्घकालीन अवसर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम होती है।

साहित्य पुनरावलोकन

पी० आर० दत्ता , एम मुरूगई और ड०लयू वी डोमिनिक 2012 – के लेख इन इडियाज इम्प्लायमेन्ट गांरठी स्कीम गांरटी इम्प्लायन्ट के अध्ययन करने पर इस बाते का पता चला कि सभी राज्यो मे रोजगार की पर्याप्त मांग पूरी नहीं होती। गरीब परिवार को ज्यादा काम की आवश्यकता है। गरीब परिवार एवं पिछड़ी जातियाँ ज्यादा काम मांगती हैं। निर्धन राज्यो मे मांगे पूरी नहोने के कारण शिकायत ज्यादा है। यह योजना महिलाओं को आकर्षित करती है।

माघव प्रसाद गुप्ता 2016– के मनरेगा पंचायती राज्य एवं जनजातियों विकास के अध्ययन से पता चलता हैं की भारत मे ग्रामीण विकास के लिए आजीविका जल ,जंगल जमीन के प्रबंध मे जनजातीय सहभागिता का महत्वपूर्ण स्थान है। पंचायती राज्य संस्था कार्य प्रणाली मे सुधार लाकर कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। जनजातिय को अपने गाँव एवं गाँव के आस–पास स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। साथ ही स्थायी परिसम्पतियो के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ते है। पंचायती राज्य व्यवस्था के कार्य प्रणाली मे सुधार कर स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं परिसम्पतिया बढ़ायी जा सकती है।

धनजय सिंह 2015 – ग्रामीण विकास एवं राज्य नामक पुस्तक मे यह स्पष्ट किया की राज्य द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमो से लोगो को गाँव मे ही स्वच्छ पेयजल सड़क एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हुई जो लोगो के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण है इन्होने विकास कार्यक्रम कि असफलता का कारण भ्रस्टाचार जाति वाद एवं भाई–भतीजे बाद को बताया।

शोध का उद्देश्य

1. रोजगार के अवसरों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्र में आय में वृद्धि की तुलनात्मक अध्ययन
3. आधारभूत संरचना के विकास का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. कृषि के विकास में मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना।
6. बोकारो तथा रामगढ़ जिले में ग्रामीण क्षेत्र मनरेगा के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना।
7. मनरेगा के अंतर्गत आने वाली चुनौतियों तथा उनका समाधान की पहचान कर सुझाव देना।

शोध परिकल्पना

1. बोकारो तथा रामगढ़ जिले में रोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि हुई।
2. मनरेगा के माध्यम महिलाओं की आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त किया जा रहा है।
3. मनरेगा योजना ग्रामीण में आधारभूत संरचना विकसीत हुई जिससे ग्रामीण क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास की संभवना है।
4. मनरेगा योजना में वितीय तथा प्रशासनिक समस्याओं मनरेगा के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव को सीमित कर रही है।

शोध क्षेत्र एवं काल

झारखण्ड राज्य के बोकारो तथा रामगढ़ जिले में मनरेगा के पिछले पांच वितीय वर्ष 2018–2019 से 2022–2023 तक मनरेगा के कार्यो का वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन करना। इसमें मनरेगा के वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है।

शोध का महत्व

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित महत्व है।

1. ग्रामीण गरीबी निवारण का मूल्यांकन – इस शोध के माध्यम से दोनो जिलों में मनरेगा का ग्रामीण गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को जानने के लिए तुलनात्मक अध्ययन से सहायता मिलेगा।
2. महिलाओं की भागीदारी – इस शोध पत्र के माध्यम से दोनो जिलों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी उनकी आय तथा आय बढ़ने से सामाजिक स्थिति एवं निर्णय क्षमता के प्रभाव को जानने को मौका मिला।
3. आधारभूत संरचना का विकास– मनरेगा योजना के अंतर्गत आधारभूत संरचना का निर्माण जिनमें जल संग्रहण एवं संचयन, भूमि विकास एवं सुधार ग्रामीण संर्पक सड़क स्वच्छता से संबंधित कार्य एवं आंगनबाड़ी मुख्य है उनके प्रभाव तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में

इनके महत्व को जानने का अवसर मिलता है।

4. मनरेगा की समस्याओं को जानकर समाधान हेतु सुझाव– इस शोध के माध्यम बोकारो तथा रामगढ़ जिले की प्रमुख समस्याओं को जानने का अवसर प्राप्त होता है। जिससे उनके उचित समाधान हेतु सुझाव देकर मनरेगा को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
5. भावी नीति बनाने में सहायक – इस शोध के माध्यम से मनरेगा की समस्याओं को जानने के बाद उनके उचित समाधान हेतु सुझाव प्राप्त होते है जिसकी मदद से मनरेगा को भविष्य में अधिक लाभदायी बनाने हेतु नीति बनायी जा सकती है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ों के रूप में सरकार के आधिकारिक वेबसाइट से वितीय वर्ष 2018–2019 से 2022–2023 तक के मनरेगा के कार्यो का तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण किया जायेगा। तुलनात्मक विश्लेषण में सांख्यिकीय उपकरण प्रतिशत, औसत एवं सहसंबंध का उपयोग किया जायेगा।

व्याख्या एवं विश्लेषण

मनरेगा के कार्यो का वर्णानात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन करके मनेरगा के ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव को जानने का प्रयास किया जायेगा।

मनरेगा का आर्थिक प्रभाव–

प्रति व्यक्ति रोजगार (औसत) का विवरण

(वितीय वर्ष 2018–2019से 2022–2023 तक)

वितीय वर्ष	बोकारो	रामगढ़	तुलनात्मक वृद्धि प्रतिशत में
2018–2019	33.93	34.16	0.6
2019–2020	34.09	37.35	9.39
2020–2021	33.75	38.94	15.37
2022–2023	33.67	40.51	20.31

उपर्युक्त आंकड़ों में 2018–2019 में प्रतिव्यक्ति 33.93 व्यक्ति एक वितीय वर्ष में रोजगार दिये गए जबकि रामगढ़ में 34.16 व्यक्ति को रोजगार दिया गया। जो बोकारो की तुलना में रामगढ़ जिले में मात्र 0.6 प्रतिशत है।

2019–2020 में बोकारो में 34.09 दिवस तथा रामगढ़ जिले में 37.35 दिवस रहा जो बोकारो जिला की तुलना में 9.09 प्रतिशत अधिक है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति रोजगार दिवस की वृद्धि 2022–2023 में दर्ज की गई जो बोकारो की तुलना में बोकारो जिले के तुलना में 20.31 प्रतिशत अधिक है।

इस तरह से देखा जाय तो बोकारो जिला की तुलना में रामगढ़ जिला में प्रति व्यक्ति रोजगार औसत ज्यादा है।

मनरेगा योजना में 100 दिन काम करने वाले परिवारों की औसत संख्या (प्रति प्रखण्ड औसत)

(वितीय वर्ष 2018–2019से 2022–2023 तक)

वितीय वर्ष	बोकारो परिवारों की संख्या	रामगढ़ परिवारों की संख्या	प्रतिशत (तुलनात्मक)
2018–2019	65	179	175
2019–2020	28	197	603
2020–2021	229	747	226
2021–2022	377	823	118
2022–2023	345	650	88.4

उपर्युक्त आंकड़ो के माध्यम से यह पता चलता है कि वितीय वर्ष 2018–2019 में बोकारो जिला में 65 तथा रामगढ़ जिला में 179, 2019–2020 में बोकारो जिला में 28 जबकि रामगढ़ जिला में 197 परिवारों के 100 दिन रोजगार पाया वही 2020–2021 बोकारो जिला में 229 परिवार तथा रामगढ़ जिले में 747 परिवारो ने मनरेगा के तहत 100 दिन काम किया 2021–2022 में भी बोकारो की तुलना में रामगढ़ में कार्यरत परिवार की संख्या दुगुना से अधिक रहा।

इस तरह देखा जाय तो बोकारों की तुलना में रामगढ़ जिले में 100 दिन काम पाने वालों की संख्या अधिक रही

प्रतिव्यक्ति रोजगार सृजन एवं आय – मनरेगा योजना में इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों को प्रतिपरिवार अधिकतम 100 दिन एक वितीय वर्ष में रोजगार देने का प्रावधान है। यह प्रावधान सुखाग्रस्त क्षेत्र एवं प्राकृतिक आपदा के (बाढ़, आकाल) के समय बढ़कर अधिकतम 150 दिन रोजगार का प्रावधान है।

प्रतिव्यक्ति रोजगार सृजन एवं आय का विवरण

(वितीय वर्ष 2018–2019से 2022–2023 तक)

वितीय वर्ष	बोकारो जिला		रामगढ़ जिला	
	प्रतिव्यक्ति रोजगार दिवस	कुल आय	प्रतिव्यक्ति रोजगार दिवस	कुल आय
2018–2019	33.43	5700.43	34.16	5738.91
2019–2020	34.09	5828.56	37.15	6387.22
2020–2021	34.76	6743.67	36.71	7121.32
2021–2022	33.76	7591.64	38.94	8761.01
2022–2023	33.67	7856.86	40.52	9397.26

उपर्युक्त तालिका में बोकारो जिला के पिछले पांच वितीय वर्ष का औसत प्रतिव्यक्ति रोजगार 33.94 दिवस है। जबकि रामगढ़ जिले में यह औसत 37.49 है। इस तरह स्पष्ट है कि बोकारो जिला की तुलना में रामगढ़ जिला में प्रतिव्यक्ति रोजगार दिवस अधिक है। रोजगार दिवस अधिक होने से आय में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगो की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। रोजगार दिवस एवं आय के बीच में बोकारो जिला की तुलना में रामगढ़ जिले में सहसंबंध अधिक मजबूत है।

परियोजना कार्य

कुल किये गये कार्य –परियोजना के आधार बोकारो जिला में 2018–2019 से 2022–2023 तक 11072 कार्य पूर्ण किये जब कि रामगढ़ जिले 2018–2019 से 2022–2023 13056 परियोजना पूर्ण गई। क्योंकि रामगढ़ जिला एक ग्रामीण जिला है जहां की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है एवं मनरेगा में कृषि से संबंधित कार्यो की प्रधानता होती है। कृषि के विकास से जहां लोगों की आय में वृद्धि होगी आय बढ़ने पर उनका जीवन स्तर एवं पारिवारिक आय बढ़ेगी।

कृषि के विकास से लोगो को पर्याप्त आय एवं रोजगार मिलने में बेरोजगारी कम होगी तथा पलायन भी रूकेगा।

मनरेगा का कृषि के विकास पर प्रभाव

मनरेगा योजना में आधारभूत संरचना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क, नाली एवं कच्चा मोरम पथ बनने से जहाँ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवश्यक एवं कृषि संबंधी यंत्रो एवं उपकरणो को लाने ले जाने में कम समय एवं लागत व्यय करना होगा जिसके परिणामस्वरूप किसानों की कृषि लागत कम होगी तो दुसरी ओर उत्पादित अनाज को सड़को के माध्यम से शहर एवं कस्बो की मंडियों राज्य में परती भूमिका प्रतिशत करीब 25 प्रतिशत है। राज्य की करीब 69 प्रतिशत जोते सीमांत (एक हेक्टेयर से कम) तथा 15.5 प्रतिशत छोटी जोते है। राज्य की मुख्य फसल धान है। यहाँ धान मुख्य फसल के रूप में उपजायी जाती है।

मनरेगा योजना के तहत किये गये कुल कार्यो का विवरण

(वितीय वर्ष 2018–2019से 2022–2023 तक)

	बोकारो जिला						रामगढ़ जिला					
कार्यो का विवरण	2018–2019	2019–2020	2020–2021	2021–2022	2022–2023	कुल	2018–2019	2019–2020	2020–2021	2020–2023	2022–2023	योग
भूमि विकास	02	01	03	06	07	19	894	252	115	287	94	1642
सूक्ष्म सिंचाई योजना	00	00	00	04	05	09	03	11	186	273	18	491

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बोकारो जिला की तूलना में रामगढ़ जिले में सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं भूमि विकास से संबंधित कार्य अधिक हुये। क्योंकि रामगढ़ जिला एक कृषि प्रधान जिला है यहाँ पर कृषि के अलावे रोजगार के अन्य विकल्प सीमित है। साथ ही

मनरेगा योजना में कृषि से संबंधित कार्य अधिक किये जाते है। जबकि बोकारो जिला एक औद्योगिक प्रधान जिला है यहाँ पर रोजगार के अन्य विकल्प उपलब्ध है। इसलिए मनरेगा के तरफ अधिकारियों का ध्यान कम है।
सामाजिक विकास पर प्रभाव–

महिलाओं द्वारा प्राप्त रोजगार दिवस प्रति प्रखण्ड विवरण

(वितीय वर्ष 2018–2019 से 2022–2023)

वितीय वर्ष	बोकारो जिला		रामगढ़ जिला	
	रोजगार दिवस	रोजगार प्रतिशत	रोजगार दिवस	रोजगार प्रतिशत
2018–2019	93193	35.11	85273	39.02
2019–2020	111990	39.78	99848	40.74
2020–2021	195828	40.38	158090	43.87
2021–2022	215142	45.88	197443	46.95
2022–2023	194430	52.90	173329	47.34

वितीय वर्ष 2018 –2019 से 2022–2023 तक महिलाओं को प्राप्त रोजगार दिवस प्रति प्रखण्ड महिलाओं के प्रतिशत 2018–2019 में बोकारो जिले 35.11 जबकि रामगढ़ जिले 39.02 महिलाओं को रोजगार 2019–2020 बोकारो जिले में 39.78 प्रतिशत जबकि रामगढ़ जिले 40.74 प्रतिशत जबकि 2020–2021 में बोकारो जिले में 40.38 प्रतिशत तथा रामगढ़ जिले में 43.87 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिये गये 2021–2022 में बोकारो जिले में 45.88 प्रतिशत जबकि रामगढ़ जिले 46.95 प्रतिशत, 2022–2023 बोकारो जिले में 52.90 तथा रामगढ़ जिले में 47.34 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया गया विश्लेषण से स्पष्ट है कि बोकारो जिला के तुलना में रामगढ़ जिले के महिलाओं को ज्यादा रोजगार दिये गये।

रोजगार का सामाजिक स्थिति से संबंध –

रोजगार एवं मनुष्य की सामाजिक स्थिति में सीधा संबंध होता है। रोजगार प्राप्त होने से हमे धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति ये हमे जीवन के सारे भौतिक संसाधन प्राप्त होते है। जिससे समाज में हमारा स्टेटस बढ़ता है। आर्थिक रूप से मजबूत होने पर हमें आत्म संतुष्टि मिलती तथा आत्मविश्वास बढ़ता है।
हम अपने ज्ञान एवं कौशल के विकास से रोजगार के अच्छे अवसर एवं अच्छे वेतन प्राप्त कर सकते है।
रोजगार का दीर्घकालीन एवं उच्च पद का होना भी समाज में हमारी प्रतिष्ठा पर चार चाँद लग।
जबकि बेरोजगारी से व्यक्ति में नकारात्मकता आती है। बेरोजगारी व्यक्ति को न तो समाज में कोई इज्जत मिलती है। न ही महत्व
मनरेगा योजना ग्रामीण गरीब बेरोजगारी व्यक्ति को एक निश्चित समय तक काम की गारंटी देकर निश्चत आय प्राप्त करने का साधन देती है। जिससे मनरेगा लाभार्थी को समाज में भौतिक संसाधन उपलब्ध होते है जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार होता है। तथा समाज में लोग सम्मान देते है।

शोध अध्ययन से प्राप्त बोकारो तथा रामगढ़ जिले मुख्य समस्याएं

1. रोजगार के अवसर में कमी।
2. मजदूरी दर का कम होना।
3. समय पर मजदूरी भुगतान का अभाव।
4. भ्रष्टाचार
5. कार्यस्थल पर मिलने सुविधाओं का अभाव
6. महिलाओं के भागीदारी में कमी
7. जागरूकता का अभाव
8. प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव
9. अधिकारियों के जबावदेही में कमी
10. नियमित सोशल ऑडिट का ना होना।
11. बजट में कमी

मुख्य सुझाव

1ण शोध क्षेत्र बोकारो तथा रामगढ़ जिले के ग्रामीण के लिए रोजगार सृजन के नये विकल्प जिनमे मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य विकल्पों पर जोर देकर रोजगार बढ़ाना चाहिए।

2ण कृषि क्षेत्र में विकास हेतु बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु पौधारोपण तथा बागवानी पर जोर दिया जाना चाहिए।
3ण कार्यस्थल में उचित प्रावधानों के अनुसार सुविधाओं को दिया जाना चाहिए। कार्यस्थल में सुविधाओं के बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए प्रेरित होंगे।
4ण मनरेगा अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आधुनिक संचार तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे की मनरेगा योजना में नवीन तकनीक का उपयोग कर मनरेगा योजना की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।
5ण ग्रामीण क्षेत्र में लोगो को जागरूक करने के लिए स्थानीय भाषा से स्थानीय लोगो की मदद से मनरेगा योजना का प्रचार–प्रसार घर–घर जाकर करना चाहिए।
6ण ग्रामीण क्षेत्र में लोगो को जागरूक करने के लिए स्थानीय भाषा से स्थानीय लोगो की मदद से मनरेगा योजना का प्रचार–प्रसार घर–घर जाकर करना चाहिए।
7ण केन्द्र सरकार को राज्य सरकारो (झारखण्ड सरकार) को उचित एवं पर्याप्त बजट समय पर उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे की ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का पर्याप्त विकास, मजदूरो को मजदूरी भुगतान समय पर मिल सके।
8ण भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नियमित जांच हेतु कर्मचारियों की बहाली तथा तय एवं निश्चित समय पर सोशल ऑडिट एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तंत्र से करवाकर योजना के संचालन में कमी को दूर कर मनरेगा योजना को अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाया जा सकता है।
9ण मनरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु महिलाओं की सुरक्षा, शौचालय तथा बच्चो के रहने तथा खेलने का उचित व्यवस्था को कडाई से लागू किया जाना चाहिए।
10ण मनरेगा योजना के सुचारू संचालन हेतु मनरेगा के कर्मचारियों एवं अधिकारियों से जवाबदेह होना चाहिए। मनरेगा योजना के प्रति लापरवाह कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर कड़ी कारवायी करनी चाहिए जिससे मनरेगा योजना के अंतर्गत आधारभूत संरचना का विकास होगा रोजगार बढ़ेगा तथा आय बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगो की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत होगी।

निष्कर्ष

मनरेगा योजना ग्रामीण गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना रोजगार बढ़ाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास कृषि से संबंधित कार्य करने के फलस्वरूप रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। आधारभूत संरचना के विकास से रोजगार के अन्य साधन एवं आय में वृद्धि होती है। जिससे लोगो का आर्थिक एवं सामाजिक विकास उन्नत होता है।
मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र रामगढ़ एवं बोकारो जिले में बेरोजगारी एवं गरीबी दूर करने में कुछ हद तक सफल हुई। किन्तु मनरेगा योजना की कुछ मुख्य समस्याएं जो प्रशासनिक एवं वितीय है। आपेक्षित सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहे है। इन समस्याओं को दूर करने हेतु सुझाव दिये गये। जिससे कि मनरेगा योजना को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. अग्रवाल अरूण एवं स्वाती श्रीवास्तवः 2023; झारखण्ड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन सीरिज पृ सं –14
2. अग्रवाल अरूण एवं स्वाती श्रीवास्तवः 2023; झारखण्ड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन सीरिज पृ सं –11
3. शर्मा धर्मराजः2019; भारत निर्माण एवं मनरेगा, रावत पब्लिकेशन जयपुर पृ सं –51
4. डॉ गौड निमिशा ;2023ः – मनरेगा ग्रामीण विकास की सामाजिक आर्थिक योजना, साहित्यागार, जयपुर
5. डॉ सुमन;जून 2009ः– विकास पर्यावरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था ,आलोक भारतीय प्रकाशन, पटना
6. भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर प्रतिवेदन
7. सिंह धनंनजय ग्रामीण विकास एवं राज्य प्रग्रेसिव बुक सेंटर बाराणसी
8. गुप्ता माधव प्रसाद 'मनरेगा पंचायती राज जनजातीय विकास' रावत पब्लिकेशन जयपुर
9. दत्ता पी, आर मुरिया, एम रोपलेन्स एण्ड डब्लू वी डोमोनिक – इज इंडियनस इमप्लॉमेंट गारंटी स्कीम, इन गारंटी इमप्लॉमेंट पॉलिशी? रिर्सच वसिंग डी० सी
10. www.nrega.nic.in
11. https://www.jharkhand.gov.in